गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 110
दि. 20.08.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

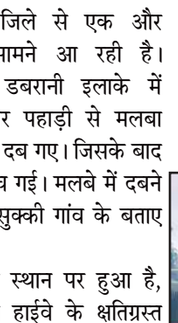

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जी को त्रिपुरा के विकास में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए याद किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि जनसेवा के प्रति उनका जुनून, गरीबों को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पण हमें निरंतर प्रेरित करते हैं।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से नई दिल्ली में भेंट की, सीमा पर शांति और स्थिरता पर मुलाकात में हुई चर्चा

- प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता के महत्व पर बल दिया
- प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष कजान में राष्ट्रपति षी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में स्थिर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया
- प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति षी के निमंत्रण को स्वीकार किया
- प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि स्थिर, आशानुरूप और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे

(जीएनएस)।

चीन के विदेश मंत्री और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य श्री वांग यी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

श्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी को तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग का संदेश और निमंत्रण दिया। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक और विशेष प्रतिनिधियों की 24 वीं बैठक के बारे में अपने सकारात्मक मूल्यांकन को भी साझा किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल के साथ इस बैठक की सह-अध्यक्षता की थी।

प्रधानमंत्री ने सीमा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, तर्कसंगत और आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की वचनबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष कजान में चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में स्थिर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। ये संबंध आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता से निर्देशित हैं।

प्रधानमंत्री से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मुलाकात

आत्मनिर्भरता से अंतरिक्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निहित है भारत की सफलता का मार्ग: प्रधानमंत्री

भारत को भविष्य के मिशनों का नेतृत्व करने के लिए तैयार 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों का समूह बनाने की आवश्यकता है: प्रधानमंत्री

भारत के समक्ष अब दो रणनीतिक मिशन हैं– अंतरिक्ष केंद्र और गगनयान: प्रधानमंत्री

अंतरिक्ष यात्री शुक्ला की यात्रा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं की दिशा में केवल पहला कदम है: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनकी अंतरिक्ष यात्रा के परिवर्तनकारी अनुभव के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण यात्रा करने के बाद व्यक्ति को बड़ा बदलाव महसूस होना चाहिए। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि अंतरिक्ष यात्री इस परिवर्तन को कैसे समझते हैं

और किस प्रकार उसका अनुभव करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रश्नों के उत्तर में शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष का वातावरण एकदम अलग होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का अभाव प्रमुख कारक है।

प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि क्या यात्रा के दौरान बैठने की व्यवस्था एक ही प्रकार की व्यवस्था में 23-24 घंटे बिताने पड़ते हैं। शुभांशु शुक्ला ने इसकी भी पुष्टि की और उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों से उठ सकते हैं और यात्रा के लिए पहने गए विशेष सूट से बाहर आ सकते हैं तथा वे कैप्सूल के भीतर खुलकर घूम सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत के दौरान अंतरिक्ष यात्रा के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए पूछा कि क्या कैप्सूल में पर्याप्त जगह होती है, तो शुभांशु शुक्ला ने बताया कि हालांकि वह बहुत विशाल स्थान नहीं था फिर भी वहां कुछ जगह अवश्य उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कैप्सूल तो लड़ाकू विमान के कॉकपिट से भी ज्यादा आरामदायक लग रहा था, तो श्री शुक्ला ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "यह तो उससे भी बेहतर है, सर।" इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री मोदी को अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में भी जानकारी दी। शुभांशु शुक्ला ने बताया कि वहां पर हृदय गति अत्यंत धीमी हो जाती है और शरीर वहां की परिस्थितियों में कई प्रकार से स्वयं को समायोजित करता है।

उत्तरकाशी में एक और बड़ा हादसा, डबरानी इलाके में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने से दो लोग दबे

(जीएनएस)।

उत्तरकाशी जिले से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी के डबरानी इलाके में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने से दो लोग दब गए। जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मलबे में दबने वाले दो युवक सुक्की गांव के बताए जा रहे हैं।

हादसा उसी स्थान पर हुआ है, जहां पर गंगोत्री हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीन युवक पैदल ही सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी भूस्खलन हो गया और एक युवक भागने में कामयाब हुआ लेकिन दो युवक मलबे में दब गए।

दोनों युवक सुक्की गांव के हैं। इस बीच ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रशासन ऐसी स्थिति में किसी को डेंजर जोन से पैदल जाने के लिए मना कर रही है। इस बीच ये घटना हो गई। जिसको

लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पांच अगस्त को हरसिल घाटी में आई आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त हो रखा है। नेताला से लेकर धराली तक कई जगह सड़क ही गायब है। सबसे बड़ी दिक्कत डबराणी क्षेत्र में है। जहां करीब 250 मीटर हिस्सा बह गया था, जिसके बाद यहां बीआरओ की मशीने हाईवे खोलने में लगी हुई है।

इसी जगह पर जेसीबी और अन्य मशीनें वेकल्पिक मार्ग खोलने में जुटी है। हालांकि मौसम बार बार खलल डाल रहा है। सडक मार्ग न होने की वजह से स्थानीय लोग पैदल ही सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये हादसा हो गया।

जहां पर सड़क मार्ग नहीं है और भागीरथी को पार करना पड़ रहा है। वहां पर रेस्क्यू बोट लगाई गई है। ग्रामीणों को रेस्क्यू बोट से नदी पार कराई जा रही है। साथ ही सिलेंडर, राशन आदि कई जरुरी सामान भी बोट से ही पार कराए जा रहे हैं।

भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

हमारे कूटनीतिक प्रयास हमारी घरेलू आवश्यकताओं और 2047 तक विकसित भारत बनने के हमारे उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए: राष्ट्रपति मुर्मु

(जीएनएस)।

भारतीय विदेश सेवा (2024 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज (19 अगस्त, 2025) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी यात्रा शुरू करते समय सभ्यतागत ज्ञान के मूल्योंझ शांति, बहुलवाद, अहिंसा और संवाद आदि को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। साथ ही, उन्हें अपने सामने आने वाली हर संस्कृति के विचारों, लोगों और दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके आसपास की दुनिया भू-राजनीतिक बदलावों, डिजिटल क्रांति,

जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षवाद के संदर्भ में तेजी से बदलाव देख रही है। युवा अधिकारियों के रूप में, उनकी चपलता और अनुकूलनशीलता हमारी सफलता की कुंजी होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच असमानता से उत्पन्न समस्याएं हों, सीमा पार आतंकवाद का खतरा हो या जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ हों, भारत आज विश्व की प्रमुख चुनौतियों के समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि एक निरंतर उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है। हमारी आवाज का महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि राजनयिकों के रूप में, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भारत का पहला चेहरा होंगे जिसे दुनिया उनके शब्दों, कार्यों और मूल्यों में देखेगी।

राष्ट्रपति ने आज के समय में सांस्कृतिक कूटनीति के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हृदय और आत्मा से बने संबंध हमेशा मजबूत होते हैं। चाहे वह योग हो, आयुर्वेद हो, श्रीअन्न हों या भारत की संगीत, कलात्मक, भाषाई और आध्यात्मिक परंपराएं हों, अधिक रचनात्मक और महत्वाकांक्षी प्रयास इस विशाल विरासत को विदेशों में प्रदर्शित और प्रचारित करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे

केंद्र द्वारा 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'अन्न-चक्र' आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत "अन्न-चक्र" आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक को 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया था।

कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:- 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानि पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम, बिहार, सिक्किम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नगालैंड, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा में लागू है। मणिपुर में यह लागू नहीं है।

क्या है PM, CM और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक? जिसे लोकसभा में आज पेश करेगी मोदी सरकार

मोदी सरकार राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसी क्रम में, बुधवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए एक कानूनी स्ट्रक्चर तैयार करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार शाम लोकसभा महासचिव को इन विधेयकों को पेश किए जाने की जानकारी दी। सरकार द्वारा 130वां संविधान विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करें।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की

- राष्ट्रीय आयुष मिशन और आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लाखों लोगों तक आयुष स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं: केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव
- केंद्रीय मंत्री श्री जाधव ने कहा, "आयुष उद्योग 200 अरब डॉलर के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है"
- आयुष मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में आयुष प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण, विस्तार, वैश्विक पहुंच और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के समिति के सांसदों ने भाग लिया।

संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों में डॉ. स्वामी सचिदानंद हरि

साक्षी, डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्रीमती. ज्योत्सना सी महंत, श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, श्री परषोत्तम रूपाला, श्री अष्टिकर पाटिल नागेश बापुराव, श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, श्री लावु श्री कृष्ण देवरायलू, श्री सदानंद म्हालू शेट तनावडे, श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई और श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने बैठक में भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने एक महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय के एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने के बाद पहली बार एक समर्पित संसदीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कदम आयुष से संबंधित मामलों पर केंद्रित चर्चा, बेहतर ध्यान और मजबूत नीतिगत दिशा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह अधिक समग्र और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा देने में मंत्रालय की भूमिका को और बढ़ाएगा।

आयुष के विकास पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री जाधव ने कहा, "प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आयुष अनुसंधान परिषदों, वैधानिक निकायों और राष्ट्रीय संस्थानों के एक मजबूत नेटवर्क के साथ तेजी से विकसित हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत गांधीनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होगी सहकारी अग्रणियों की कार्यशाला

गांधीनगर, 19 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत बुधवार, 20 अगस्त को गांधीनगर में आयोजित होने वाले सहकारी अग्रणियों की कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 ह्यसहकारिताएं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैंह्व थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य सहकारी क्षेत्र में समावेशी, टिकाऊ और लचीले ढांचे तथा संगठनों का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश भर में ह्यसहकार से समृद्धिह्व के मंत्र के साथ यह अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य के सहकारिता, पशुपालन, गौ संवर्धन और मत्स्योद्योग विभाग ने इस

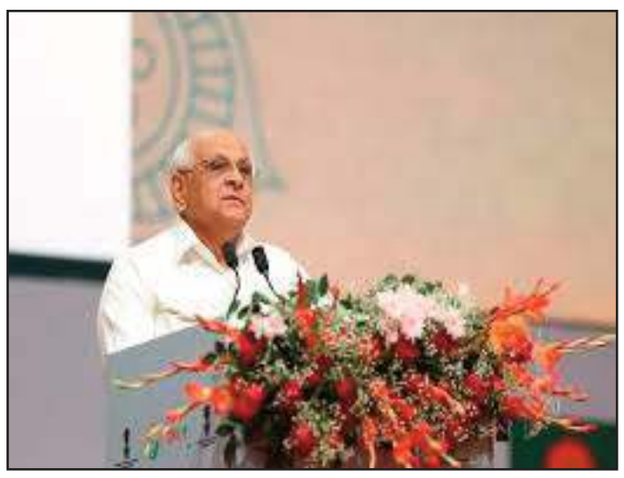

कार्यशाला का आयोजन किया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार, 20 अगस्त को सुबह 11:00 बजे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी अतिथि विशेष के रूप में मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मुळुभाई बेरा, सहकारिता राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री मुकेशभाई पटेल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

इतना ही नहीं, गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री अजयभाई पटेल, इफको के चेयरमैन श्री दिलीपभाई संघाणी तथा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के चेयरमैन श्री अशोकभाई चौधरी भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में राज्य भर की जिला मध्यस्थ सहकारी बैंकों के निदेशक, जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के निदेशक और गुजकोमासोल एवं खेती बैंक के निदेशक सहित राज्य के सहकारी नेता भी हिस्सा लेंगे।

सम्पादकीय

उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी अलास्का वार्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की अलास्का की बैठक पर सारी दुनिया की नजरें थीं। पिछले तीन साल से चले आ रहे रूस, यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर उम्मीदें लगाईं जा रही थीं। स्थायी शांति न भी होती तो इतना तो हो सकता था कि युद्ध विराम तो हो जाता। पर सारी उम्मीद टूट गई। बेशक वुछ मुद्दों पर जरूर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की सहमति बनी पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। तीन साल से अलग-थलग किए गए पुतिन का ट्रंप ने न सिर्प खुले दिल से स्वागत किया, बल्कि लाल कालीन बिछाकर उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान भी किया। हालांकि जिस मुद्दे के लिए यह अहम बैठक हुई थी उस पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। ट्रंप-पुतिन मुलाकात से यूक्रेन मुद्दे पर कोई तत्काल हल नहीं निकला, बावजूद यह मुलाकात खास रही। रूस के यूक्रेन पर हमले और युद्ध अपराधों के आरोपों के चलते पुतिन पामिी दुनिया से अलग-थलग पड़ गए थे। इस मुलाकात ने उन्हें अचानक वैश्विक वेंद्र में वापस ला दिया। अमेरिका के सैन्य अड्डे पर दोनों नेताओं का बगल-बगल खड़े होकर एक-दूसरे की तारीफ करना, बातचीत करना और यहां तक कि ट्रंप की लियोजीन में साथ बैठना ये सब ऐसे दृश्य थे जो अमेरिका-रूस संबंधों के इतिहास में कम ही देखे गए। दुनिया भर की मीडिया एक प्रोस कांप्रेंस की उम्मीद कर रही थी, लेकिन दोनों नेताओं ने सिर्प बयान दिए और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी और यहां तक दावा किया था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को रूकवा देंगे। हालांकि पुतिन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया था। पुतिन के लिए यह बैठक किसी जीत से कम नहीं थी। बिना कोई रियायत दिए उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर वुसा से सम्मान और स्वीवृति मिल गई। इस पूरी कवायद में यूक्रेन की भूमिका हाशिए पर रही। इस बैठक के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादिमीर जेलेंस्की को आमंत्रित तक नहीं किया गया। अलास्का में ट्रंप पुतिन बैठक को वैश्विक मीडिया शांति की दिशा में बहुत भरोसे के साथ नहीं देख रहा है। रूसी मीडिया ने पुतिन की वूटनीतिक जीत का सुबूत माना, यूरोपीय मीडिया ने उम्मीद और आशंका दोनों जताईं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और घरेलू अमेरिकी राजनीतिक हल्कों में चर्चा का बड़ा हिस्सा ट्रंप की व्यक्तिगत शैली और उनकी मसखरी नेता जैसी छवि पर वेंद्रित रहा। न्यूयार्व टाइम्स ने अपेक्षावृत संशयपूर्ण रुख अपनाते हुए सवाल उठाया, क्या यह वार्ता सिर्प फोटोशूट और अल्पकालिक सुर्खियां थीं या वास्तव में संघर्ष विराम की दिशा में ठोस कदम? अमेरिकी खुफिया व रक्षा हल्कों में आशंका है कि पुतिन ने बैठक का इस्तेमाल वैश्विक मंच पर अपनी छवि सुधारने और यह दिखाने के लिए किया कि अमेरिका अंततः रूस से बातचीत करने पर मजबूर हुआ। वाशिगटन पोस्ट ने राजनीतिक दांव बताते हुए सवाल उठाया कि क्या ट्रंप का मूड आधारित नेतृत्व अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति को कमजोर कर रहा है। दोनों अखबारों ने लिखा कि ट्रंप के पैसले उनके मूड पर निर्भर हैं आज खुश तो शांति की बात करेंगे, पर गुस्से में होंगे तो पलट जाएंगे। एमएसएन ने ट्रंप को रियलिटी शो का होस्ट स्टार करार दिया। नोबेल की चाह में बेकरार राजनेता वैश्विक मंच पर कोई ड्रामा कर सकता है। ट्रंप वैश्विक मंच व वैश्विक राजनीति शो मैनशिप में बदल रहे हैं। सीएनएन ने कहा, ट्रंप शांति की ओर बढ़ रहे हैं पर उनका अप्रात्याशित रुख सब पर भारी है। वहीं ब्रिटिश अखबार व गार्डियन ने वार्ता को राजनीतिक विडम्बना बताया।

लिखा : वार्ता ऐसे समय हुई जब आर्वटिक क्षेत्र में रूस, अमेरिका और चीन के बीच प्राभुत्व की दौड़ तेज है, सुरक्षा विशेषज्ञों को यह कदम अमेरिका की आर्टिक रणनीति में नरमी का संकेत लगता है। गार्डियन ने चेतावनी दी, ट्रंप की अप्रात्याशित वूटनीति से वार्ता के नतीजे भरोसेमंद नहीं माने जा सकते। उधर रूस के अखबार इजवेसित्या ने लिखा : ट्रंप को मानना पड़ा कि पुतिन के बिना यूक्रेन का भविष्य तय नहीं हो सकता। कोमरूट ने इसे रूस की वूटनीतिक वापसी बताया। टीवी चैनल आरटी ने भी बैठक को पुतिन की मजबूती और धैर्य का परिणाम करार दिया। इतना तो हम भी कह सकते हैं कि इस बैठक ने निःसंदेह ब्लादिमीर पुतिन को वैश्विक कटूनीति का अपरिहार्य खिलाड़ी बना दिया है। उम्मीद की जाती है कि रूस-यूक्रेन जंग में जो बर्प पिघलने का सिलसिला शुरू हुआ है यह आगे बढ़ेगा और अंततः यह जंग बंद होगी।

शुभांशु शुक्ला के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत का मूल पाठ

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री - आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचे हैंङ्ग

शुभांशु शुक्ला - जी सर।

प्रधानमंत्री - तो आपको कुछ चेंज फील होता होगा, जैसे मैं समझाना चाहता हूं, वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग?

शुभांशु शुक्ला - सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहां का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है।

प्रधानमंत्री - आप चाहते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है...

शुभांशु शुक्ला - वैसा ही रहता है सर।

प्रधानमंत्री - और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है?

शुभांशु शुक्ला - हां सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, तो आप अपना सीट खोलके, अपना ॅ१ल्ली२२ खोलके आप उसी कैप्सूल में आप नो ग्राउंड आप जा सकते हैं, इधर-उधर चीजें कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री - इतनी जगह है उसमें?

शुभांशु शुक्ला - बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है।

प्रधानमंत्री - मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है।

शुभांशु शुक्ला - उससे भी ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं जैसे सर पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं, और वो, लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी ४री ३ङ्ग हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं, तो फिर वही, दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप चल नहीं सकते, वापस आते हैं तो, चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा, तीसरा, हालांकि कि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है, उसको टाइम लगता है वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरमेंट है, नया वातावरण है।

प्रधानमंत्री - यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है?

शुभांशु शुक्ला - माइंड का ट्रेनिंग

है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की १ी६ृ१ल्लॅ होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी, या इतना एफर्ट लगेगा। वो वापस ये समझते हैं सर।

प्रधानमंत्री - सबसे ज्यादा समय से वहां कौन था, कितने समय तक?

शुभांशु शुक्ला - इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पर करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर, इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे।

प्रधानमंत्री - अभी वहां जो लोग मिले आपको...

शुभांशु शुक्ला - हां, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे।

प्रधानमंत्री - और आप मूंग और मेथी का महत्व क्या है?

शुभांशु शुक्ला - बहुत अच्छा है सर, मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीजों के बारे में, ाङ्गङ्ग बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पर, जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर, और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में, छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डालकर उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट्स आना शुरू हो गए थे सर। स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये जो हमारी कंट्री की ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूंगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहां पहुंच रहे हैं। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है, तो ये पृथ्वी पर भी उन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती हैं सर।

प्रधानमंत्री - पहला इस बार एक कोई भारतीय आया, तो भारतीय को देखकर के उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं?

शुभांशु शुक्ला - जी सर। मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है पिछले एक साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे, बात करने में आकर मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थे कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है। सबको ये इस बारे में जानकारी थी, और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आकर मुझसे पूछते थे कि आपका मिशन कब जा रहा है, एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवाके लिखकर लेकर गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा, आप हमें इनवाइट करेंगे लॉन्च के लिए।

वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन से पहले मांडल-बेचराजी SIR में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में तेजी

उत्तर गुजरात बन रहा नया ग्रोथ हब: MBSIR में इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन निकट उत्तर गुजरात में आगामी VGRC में मांडल-बेचराजी SIR के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे मुख्य आकर्षण का केंद्र

गांधीनगर, 19 अगस्त: मांडल-बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (**MBSIRDA**), जो मांडल-बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है, यह इन दिनों कई बड़े इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है। टइरक्क में चल रही ये परियोजनाएँ उत्तर गुजरात के इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम को और सशक्त बनाएंगी। उल्लेखनीय है कि यह प्रगति ऐसे समय हो रही है जब क्षेत्र आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (**VGRC**) उत्तर गुजरात की तैयारी कर रहा है, जिसका आयोजन 9झ10 अक्टूबर, 2025 को मेहसाणा में होगा।

विभिन्न विकास पहलों के तहत **MBSIRDA** ने बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- लगभग ₹190 करोड़ के निवेश से 33 किलोमीटर विकास योजना सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- लगभग ₹500 करोड़ की लागत से 66 किलोमीटर टाउन प्लानिंग सड़कों का निर्माण, जिसमें जलापूर्ति, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट पाइपलाइन जैसी एकीकृत सुविधाएँ शामिल हैं, पर तेजी से काम जारी है।

टइरक्कळ्ळ की ₹70 करोड़ की योजना से इन्डस्ट्रियल सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा और मजबूत, जिनमें प्रमुख प्रोजेक्ट्स शामिल हैं:

- 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक अतिरिक्त जल उपचार संयंत्र
- 4 से 15 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले तीन सीवेज उपचार संयंत्र
- उद्योगों के लिए 19 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (**CETP**)

ये दूरदर्शी परियोजनाएँ गुजरात की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत विश्वस्तरीय इन्डस्ट्रियल हब का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही सततता और पर्यावरणीय सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है।

आगामी **VGRC** उत्तर गुजरात, मेहसाणा में आयोजित होने जा रहा है, जो विश्व प्रसिद्ध वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (**VGGS**) मॉडल का विस्तार है। इसमें उत्तर गुजरात की आर्थिक मजबूती जैसे कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल उद्योगों को प्रदर्शित किया जाएगा। टइरक्क में हो रही प्रगति यह दर्शाती है कि यह क्षेत्र निवेश आकर्षित करने और समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे यह सम्मेलन में चचाओं का केंद्र बनेगा। **VGRC** का उद्देश्य व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहयोगी विकास को बढ़ावा देना है, जो गुजरात की समावेशी औद्योगिक विकास की दृष्टि को परिलक्षित करता है।

कीट नियंत्रण के लिए तकनीकी सहायता

(जीएनएस)।

ऐसा कोई विशिष्ट आँकड़ा उपलब्ध नहीं है जो दशार्ता हो कि जलवायु परिवर्तन, गर्मी, लू और टिड्डियों जैसी आपदाओं के कारण कपास और मूंग जैसी फसलों में कीटों का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप 33% या उससे अधिक हो गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और संवर्धन भी करती है, जिससे सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों से ग्रस्त क्षेत्रों को इन प्रतिकूल स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। एनआईसीआरए के अंतर्गत 12 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फसलों के लिए कीटों, रोगों और मौसम पर डेटाबेस विकसित करके, फील्ड परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों में होने वाली बीमारियों की घटनाओं का समाधान किया जा रहा है।

अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कारणों से फसल हानि के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से, सरकार किसानों को जलवायु संबंधी खतरों से बचाने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने खरीफ 2016 से प्रमुख उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) भी शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन को समर्थन देना है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना और खेती में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को अपरिहार्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे

सूखा, लगातार सूखे की स्थिति, बाढ़, ओलावृष्टि, जलप्लावन आदि के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जो फसल के बुवाई के पूर्व से लेकर फसलोपरांत नुकसान तक पूरे फसल चक्र को कवर करता है। 30 जून 2025 तक, 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, प्रीमियम में किसानों की कुल हिस्सेदारी ₹18,175.0 करोड़ थी। ₹86,755.8 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया, जिससे 14,63,73,629 किसान आवेदनों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) (पूर्व में एनएफएसएम) के अंतर्गत आईसीएआर-सीआईसीआर, नागपुर द्वारा वर्ष 2018-19 से "पिंक बॉलवर्म प्रबंधन रणनीतियों का प्रसार" परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य कपास की फसल के विभिन्न विकास चरणों के दौरान एकीकृत पिंक बॉलवर्म प्रबंधन कार्यनीतियों का प्रसार करना है, ताकि कपास में पिंक बॉलवर्म के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

इसके अतिरिक्त, आईसीएआर-केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआईसीआर) ने कीटों प्रभावित क्षेत्रों में कीटों के स्तर को कम करने के लिए फेरोमोन ट्रैप विकसित किए हैं।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

ओडिशा में हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास, 110.875 किमी) के निर्माण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 8307.74 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से ओडिशा में हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास, 110.875 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 8307.74 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत से ओडिशा में हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास - 110.875 किमी) के निर्माण को मंजूरी दे दी।

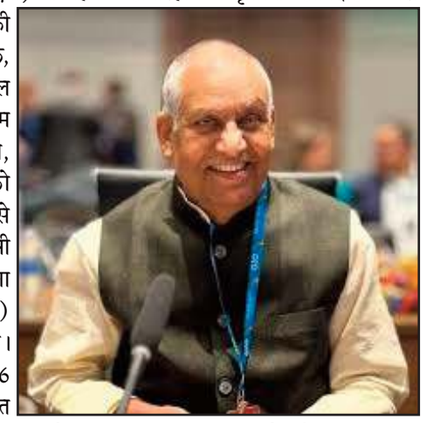

वर्तमान में, विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामेश्वर से तांगी के बीच संपर्क मार्ग पर अत्यधिक शहरीकृत शहरों खोरधा, भुवनेश्वर और कटक से होकर गुजरने वाले उच्च यातायात के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इस परियोजना को 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना कटक, भुवनेश्वर और खोरधा शहरों से भारी वाणिज्यिक यातायात को मोड़ने के जरिए ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। इससे माल ढुलाई की दक्षता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

यह परियोजना 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-55, एनएच-57 और एनएच-655) और 1 राज्य राजमार्ग (एसएच-65) को जोड़ती है, जिससे पूरे ओडिशा के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध संपर्क प्रदान होता है। इसके अतिरिक्त, उन्नत गलियारा 10 आर्थिक केंद्रों, 4 सामाजिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़कर मल्टी-मॉडल एकीकरण को बढ़ाएगा, जिससे 1 प्रमुख रेलवे स्टेशन, 1 हवाई अड्डा, 1 प्रस्तावित बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) और 2 प्रमुख बंदरगाहों के साथ उन्नत मल्टी-मॉडलता प्रदान होगी और इससे पूरे क्षेत्र में वस्तुओं और यात्रियों की तेज आवाजाही संभव होगी।

पूरा होने पर, यह बाईपास क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क को सुदृढ़ बनाएगा और व्यापार एवं औद्योगिक विकास के नए मार्ग खोलेगा। यह परियोजना लगभग 74.43 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष और 93.04 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगी और निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए अवसर उपलब्ध कराएगी।

जीआईएएचएस स्थलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति

(जीएनएस)।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में वर्तमान में तीन विश्वव्यापी महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ (जीआईएएचएस) मौजूद हैं: ओडिशा का कोरापुट क्षेत्र, केरल की कुट्टनाड कृषि प्रणाली और कश्मीर की केसर विरासत। कोरापुट क्षेत्र मुख्यतः ऊँची ढलानों पर अपनी धान की निर्वाह खेती के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ धान की विभिन्न प्रजातियों और किसानों द्वारा विकसित किस्मों की व्यापक विविधता पाई जाती है। इसमें औषधीय पौधों के समृद्ध आनुवंशिक संसाधन भी मौजूद हैं, जो स्थानीय आदिवासी समुदायों और उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। केरल की कुट्टनाड प्रणाली समुद्र तल से नीचे विशेष कृषि परिदृश्य के रूप में अलग पहचान रखती है, जिसमें धान की खेती और मछली पकड़ने के लिए आर्द्रभूमि, नारियल और खाद्य फसलों के लिए उद्यान भूमि, और मछली पकड़ने तथा सीप संग्रह के लिए अंतर्देशीय जल निकाय शामिल हैं। वहीं, कश्मीर का केसर पार्क एक समृद्ध कृषि-पशुपालन प्रणाली का

प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता पारंपरिक केसर की खेती, अंतर-फसल और जैविक कृषि पद्धतियों का उपयोग है, जो सभी स्थानीय जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

जीआईएएचएस एक एफएओ कार्यक्रम है। भारत सरकार की स्कीमें और नीतियाँ इन स्थलों को सहयोग प्रदान करती हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत सहायता प्रदान की गई है।

ओडिशा सरकार ने बताया कि कोरापुट में जैव विविधता के संरक्षण, विभिन्न फसलों की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण और ब्रांडिंग के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। इस कार्यक्रम में सामुदायिक बीज बैंकों और जैविक कृषि पद्धतियों को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत वर्तमान में अधिक उपेक्षित फसलों और अधिक प्रयोग न किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खेती के पुनरुद्धार पर केंद्रित है।

केरल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, कुट्टनाड क्षेत्र में धान के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दो कार्य चालू वर्ष की आरकेवीवाई-डीपीआर परियोजनाओं में शामिल हैं। इनमें शामिल हैं: (i) 'हरितम हरिपद' - अलप्पुझा जिले में विभिन्न पदशेखरम के इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास कार्य। (ii) 'कुट्टनाड में जलकुंभी (इचोर्निया क्रैसिप्स) के पारिस्थितिक उपयोग' पर अनुसंधान को सहायता।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

भारत सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की

कृषि उत्पादकता को बढ़ाना

प्रविष्टि तिथिः 19 अवऋ 2025 5:41ढट ु८ ढक्ह ऊॅ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जुलाई 2023 - जून 2024 के अनुसार, भारत में 46.1% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, इस क्षेत्र ने मौजूदा कीमतों पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17.8 प्रतिशत का योगदान दिया है।

भारत सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित कुछ प्रमुख स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसएनएम का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन एवं सुरक्षा तकनीकों, फसल प्रणाली-आधारित प्रदर्शनों, नई किस्मों/संकर किस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों/औजारों/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

यह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों और बीज उत्पादक एजेंसियों को परामर्श देता है कि वे आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) आदि द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की स्ट्रेस टोलरेंट/जलवायु-अनुकूल/स्मार्ट किस्मों (जलवायु परिवर्तनों की चुनौतियों से अधिक प्रभावी तरीके से निपटने के लिए) सहित नई जारी की गई उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी), स्ट्रेस टोलरेंट किस्मों (सूखा, बाढ़ और लवणता) के फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों के मल्टिप्लिकेशन के लिए ब्रीडर सीड मांगपत्र प्रस्तुत करें, ताकि किसानों को इन फसलों की किस्मों के आवश्यक बीज उपलब्ध कराए जा सकें, जिससे कृषि उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि हो सके और देश में किसानों की लाभप्रदता में भी मदद मिल सके।

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुँच बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य से मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य छोटे भू-स्वामित्व और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल इकॉनमी ऑफ स्केल की प्रतिपूर्ति के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देना भी है। इस संबंध में, राज्य सरकारों के माध्यम से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) कार्यान्वित की जा रही है। एसएमएएम के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ट्रैक्टर सहित कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)/हाई टेक हब/फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2015-16 से केंद्र प्रायोजित स्कीम प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) भी कार्यान्वित कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरक उपयोग (फर्टिगेशन के माध्यम से), श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत में कमी आती है और इस प्रकार किसानों की समग्र आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा, नीति आयोग ने वर्ष 2021 के दौरान पीडीएमसी योजना पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया8

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

भावनगर रेलवे मंडल में चलाया जा रहा है सघन स्वच्छता अभियान (फेज-II)

पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर 'स्वच्छता अभियान - 2025 (फेज-क्क)' के अंतर्गत सघन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 16 अगस्त, 2025 से पूरे भावनगर मंडल पर चलाया जा रहा है। मंडल के वेरावल, धोला, जामजोधपुर, भाणवड, भावनगर टर्मिनस इत्यादि रेलवे स्टेशनों पर उनके परिसर, कॉलोनियों, पटरियों इत्यादि पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां रेलवे कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों ने मिलकर स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सफाई कार्य कर 'स्वच्छता अभियान 2025' का सफल आयोजन किया। भावनगर डिविजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों, प्लेटफार्मों, ट्रेनों एवं कार्यालयों में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाना तथा यात्रियों में

साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भावनगर मंडल सांस्कृतिक संघ द्वारा मंडल के स्टेशनों पर रेल यात्रियों एवं कर्मचारियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी स्वच्छता संदेश दिया जा रहा है। अभियान के तहत—

- स्टेशन परिसर, यात्री प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म एवं पटरियों की गहन सफाई की जा रही है।
- यात्रियों को पॉलिथीन के उपयोग से बचने और कूड़ा निर्धारित डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- अनावश्यक कबाड़ और बेकार सामग्री की पहचान एवं निष्कासन।
- कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु प्रेरणात्मक बातचीत।
- कचरा पृथक्करण, गीला/सूखा कचरे के निस्तारण की जानकारी दी गई।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा की, 'स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी आदत बन जानी चाहिए। यात्री एवं कर्मचारी मिलकर रेलवे को स्वच्छ और सुंदर बनाएँ।' उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन और स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा रखने में अपना योगदान दें और इस अभियान को सतत रूप से सफल बनाएं।

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक सेवाओं के नए डिजिटल युग की शुरूआत की

आईटी 2.0 का आरंभ - उन्नत डाक प्रौद्योगिकी: डिजिटल इंडिया की ओर भारतीय डाक की यात्रा में एक मील का पत्थर

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के तहत और संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के मार्गदर्शन में, डाक विभाग (डीओपी) ने सफलतापूर्वक आईटी 2.0 - एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) को शुरू किया है। यह ऐतिहासिक डिजिटल उन्नयन, विभाग के 1.65 लाख डाकघरों में से प्रत्येक के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आईटी 2.0 देश के हर कोने में तेज, अधिक विश्वसनीय और नागरिक-केंद्रित डाक और वित्तीय सेवाएं लाता है, जो समावेशिता और सेवा उत्कृष्टता के लिए भारतीय डाक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

एपीटी की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

माइक्रो-सर्विसेज, ओपन एपीआई आधारित आर्किटेक्चर

सिंगल, यूनिफायड यूजर इंटरफेस

क्लाउड रेडी डिप्लॉयमेंट

बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक संपूर्ण डिजिटल समाधान

अगली पीढ़ी की कार्यक्षमता - क्यूआर-कोड भुगतान, ओटीपी आधारित डिलीवरी, आदि।

ओपन नेटवर्क सिस्टम - ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है

10-अंक के अल्फान्यूमेरिक डिजिपिन (डीआईजीआईपीआईएन) - डिलीवरी की सटीकता बढ़ाने के लिए

बेहतर रिपोर्टिंग और विश्लेषण

इसे चरणबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। कर्नाटक डाक मंडल (मई-जून 2025) में एक सफल प्रायोगिक परियोजना के बाद, प्राप्त अनुभवों को प्रणाली और रणनीति को और परिष्कृत करने के लिए शामिल किया गया। इसके बाद एक सावधानीपूर्वक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी शुरूआत की गई, जिसमें देश के सभी 23 डाक परिमंडलों को शामिल किया गया। यह प्रक्रिया 4 अगस्त 2025 को पूर्ण हुई, जब 1.70 लाख से अधिक कार्यालयों — जिसमें सभी डाकघर, मेल ऑफिस और

राष्ट्रीय सहकारी समिति नीति के उद्देश्य व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास

(जीएनएस)।

मंत्रालय ने 24 जुलाई, 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का शुभारंभ किया। यह नीति सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक रोडमैप और व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

इस नीति का मिशन अगले 10 वर्षों में 16 उद्देश्यों को प्राप्त करना है जिन्हें छह रणनीतिक मिशन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो अनुबंध-क में हैं । इसके अतिरिक्त नीति के अधिकांश बिंदु कार्यान्वयनाधीन हैं।

प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव एक सहकारी स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से संचालित व्यवसाय है जो उत्पादों को बेचने के लिए तकनीक का उपयोग करता है। इसी सिद्धांत और सहकार से समृद्धि के सिद्धांतों के आधार पर सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एक टैक्सी सेवा सहकारी संस्था को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य एक सहकारी मॉडल पर ऐप आधारित टैक्सी सेवा विकसित करना है जिससे चालक-सदस्यों और ग्राहकों, दोनों को लाभ हो। सहयोग, पारदर्शिता और साझा स्वामित्व के सिद्धांतों पर आधारित , सहकार टैक्सी का उद्देश्य पारंपरिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म का एक जन-केंद्रित विकल्प प्रदान करना है । यह ऐप अभी विकसित किया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली और गुजरात में शुरू होने की संभावना है।

इस परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सात प्रमुख सहकारी संगठनों: इफको, नेफेड, अमूल, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल और नाबार्ड के सहयोग से सहकारी समितियों के बीच सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

संशोधित बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) की धारा 19 के अनुसार, कोई भी एमएससीएस, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा आम बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा, अपने घोषित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक या एक से अधिक सहायक संस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हो सकती हैं।

इसके अलावा, समिति उपरोक्त अधिनियम की धारा 64 के अनुसार अपने धन का निवेश या जमा कर सकती है:- (i) एक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक; (ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी निगमों, सरकारी कंपनियों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी गारंटी द्वारा सुनिश्चित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में; (iii) किसी अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति के शेयरों या प्रतिभूतियों में; (iv) बहु-राज्य सहकारी समिति के समान व्यवसाय में सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था के शेयरों, प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों।

आवारा कुत्तों का खतरा : राज्य सरकार व स्थानीय निकायों को संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार

(जीएनएस)।

आवारा कुत्तों का मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि स्थानीय निकायों को संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। कुत्तों की संख्या का मानवीय और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमावली, 2023 बनाई है। यह नियमावली विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के कैप्चर-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिलीज (सीएनवीआर) दृष्टिकोण के मानकों के अनुरूप हैं। इन नियमों के तहत, स्थानीय निकाय पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

नसबंदी कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक सतत प्रक्रिया है। सचिव (पशुपालन एवं डेयरी) द्वारा 11 नवंबर, 2024 को सभी मुख्य सचिवों को एक परामर्शी जारी की गई थी। इसके बाद, 16 जुलाई, 2025 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सचिवों ने संयुक्त रूप से एक परामर्शी जारी की, जिसमें दोहराया गया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कुत्तों की संख्या के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परामर्शी में शहरी स्थानीय निकायों से पशु जन्म नियंत्रण इकाइयां स्थापित करने और व्यापक स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया गया, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों को कवर किया जाए।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों और आवारा बिल्लियों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण की विद्यमान योजना में संशोधन किया है, जिसे चालू वित्त वर्ष से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी एडब्ल्यूबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संशोधित योजना के अंतर्गत:

एबीसी नियमावली, 2023 के अनुसार एबीसी कार्यक्रम संचालित करने के लिए एसपीसीए और स्थानीय निकायों के लिए प्रति कुत्ता 800 रुपये और प्रति बिल्ली 600 रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ढांचागत सहायता: राज्य द्वारा संचालित पशु चिकित्सा अस्पतालों के लिए सर्जिकल थिएटर, केनेल और रिकवरी यूनिट जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया है।

एडब्ल्यूबीआई शहरी स्थानीय निकायों, पशु क्रूरता निवारण सोसायटी और मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को छोटे पशु आश्रय की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये तक और बड़े पशुओं के लिए 27 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए एडब्ल्यूबीआई ने कई परामर्शी और परिपत्र जारी किए हैं जो अनुलग्नक-क में दिए गए हैं।

पीएम-किसान के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) पैक्स का एकीकरण

(जीएनएस)।

सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को पीएम-किसान और अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि पीएसीएस को किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण केंद्र बनाया जा सके। इनमें शामिल हैं:-

किसान डेटाबेस के साथ ईआरपी-सक्षम अभिसरण: पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण पर केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना पीएम-किसान, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके), ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, पीडीएस आउटलेट, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप, कस्टम हायरिंग, पीएम जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), आदि जैसे राष्ट्रीय पोर्टलों को एकीकृत करके एक समान ईआरपी-आधारित मंच प्रदान करती है।

बहु-क्षेत्रीय योजना संपर्क: पीएसीएस को अनेक केन्द्रीय योजनाओं में भाग लेने के लिए भी सक्षम बनाया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स किसानों को एक ही जगह से उर्वरक, कीटनाशक और विभिन्न कृषि इनपुट उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 36,592 पैक्स को पीएमकेएसके में अपग्रेड किया जा चुका है।

सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के रूप में पीएसीएस ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं इत्यादि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करेंगे। अब तक 47,918 पैक्स ने सीएससी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है।

ग्रामीण नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए , पीएसीएस को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पी एम बी जे के) के रूप में स्थापित किया गया है । अब तक, 762 पीएसीएस को (पीएमबीआई) से स्टोर कोड प्राप्त हो चुके हैं और वे पीएमबीजेके के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

पैक्स को खुदरा पेट्रोल ओर डीजल दुकानों के लिए पात्र बनाया गया : सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के आवंटन के लिए संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में शामिल करने की अनुमति दे दी है।

थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई : मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पीएसीएस को तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों में बदलने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 5 राज्यों के 117 थोक उपभोक्ता पंप लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में बदलने के लिए सहमति दे दी है, जिनमें से 59 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू कर दिया गया है।

अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए पीएसीएस को एलपीजी वितरक के लिए पात्र बनाया गया : सरकार ने अब पीएसीएस को एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। इससे पीएसीएस को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और अपनी आय के स्रोत में विविधता लाने का विकल्प मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए पीएसीएस को पात्र बनाया गया है । राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायत और ग्राम स्तर पर संचालन एवं रखरखाव सेवाएँ प्रदान करने के लिए 539 पैक्स की पहचान ओर चयन किया गया है।

छोटे और मध्यम शहरों सहित स्टार्ट-अप के पंजीकरण को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई

एमसीए ने सीपीएसीई, एमसीए21 वी3, ई-न्यायिकरण और वास्तविक समय सहायता सुविधाओं के साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के लिए कई डिजिटल पहल लागू की

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने छोटे और मध्यम शहरों सहित पूरे देश में स्टार्ट-अप सहित कंपनियों के पंजीकरण को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

एजीआईएलई पीआरओ-एस के साथ एसपीआईसीई+ नामक एक एकीकृत नया वेब फॉर्म उपयोग में लाया गया है। यह फॉर्म 'व्यवसाय शुरू करने' से संबंधित ग्यारह सेवाएं प्रदान करता है: (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन), (iv) कर कटौती खाता संख्या (टीएएन), (v) निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकरण, (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण, (viii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संख्या, (ix) बैंक खाता संख्या, (x) व्यावसायिक कर पंजीकरण (मुंबई, कोलकाता और कर्नाटक), (xi) दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण।

अब 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली या 20 सदस्यों तक की कंपनियों, जहां कोई शेयर पूंजी लागू नहीं है, के निगमन के लिए शून्य शुल्क लिया जाएगा।

कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के नाम आरक्षण और निगमन के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) स्थापित किया गया है।

एलएलपी निगमन फॉर्म, जिसे एफआईएलएलआईपी कहा जाता है, को भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि एलएलपी के निगमन के समय ही पैन/टैन उपलब्ध कराया जा सके।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और इंटरैक्टिव स्टार्टअप इंडिया पोर्टल तथा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे देश के किसी भी हिस्से से इसे सुलभ बनाया जा सके।

स्व-प्रमाणन के साथ मान्यता के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मान्यता पुस्तिका और ट्यूटोरियल भी विकसित किए गए हैं और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत मवेशियों की नस्ल का उन्नयन

(जीएनएस)।

भारत सरकार दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) क्रियान्वित कर रही है। इसे देशी नस्ल के मवेशियों के विकास और संरक्षण, गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों के पूरक के तौर पर संचालित किया जा रहा है, जिससे किसानों के लिए दूध उत्पादन अधिक लाभकारी हो सके।

इस योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है:

उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और संधारणीय उपायों द्वारा गोजातीय पशुओं की उत्पादकता और दूध उत्पादन में वृद्धि करना।

प्रजनन के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता के सांडों के उपयोग को प्रचारित करना।

प्रजनन तंत्र सुदृढ़ करने और

किसानों के द्वार पर कृत्रिम गभार्धान सेवाएं प्रदान कर कृत्रिम गभार्धान दायरे को विस्तृत करना।

वैज्ञानिक और समग्र उपायों से स्वदेशी गाय और भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रमुख घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति, साथ ही इस योजना के तहत डेयरी कार्यों में लगे किसानों को दी जाने वाली वित्तीय और तकनीकी सहायता निम्नलिखित है:

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गभार्धान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गभार्धान (एआई) दायरे को विस्तृत करना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के वीर्य से किसानों के घर पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गभार्धान सेवाएं (एआई) प्रदान करना है। कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी भारत पशुधन/एनडीएलएम (राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन) पर वास्तविक समय में अपलोड की जाती है, जिससे कृत्रिम गभार्धान सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और कार्यक्रम से लाभान्वित किसानों की जानकारी मिलती है। अब तक 9.16 करोड़ मवेशियों को इसके दायरे में लाया गया है, 14.12 करोड़ कृत्रिम गभार्धान किए गए हैं और इस कार्यक्रम से 5.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। उत्पादकता बढ़ने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है।

सेक्स सॉर्टेड सीमेन: देश में 90 प्रतिशत तक सटीकता के साथ मादा बछड़ों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक आरंभ की गई है। इस महत्वपूर्ण तकनीक से दूध उत्पादन बढ़ने के साथ ही बेकार पशुओं की आबादी कम करने में भी मदद मिलती है। भारत में पहली बार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित सुविधाओं से देशी गायों की नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमेन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। ये सुविधाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पांच सरकारी वीर्य केंद्रों पर स्थित हैं।

पोर्टल लॉन्च : स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता प्रणाली की मजबूती में महत्वपूर्ण कदम

पोर्टल से प्रत्यायन प्रक्रिया में आसानी, सुगमता और पारदर्शिता बढ़ेगी

(जीएनएस)।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के एक घटक बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने आज आईएसओ 15189:2022 आवेदक प्रयोगशालाओं के लिए अपना नया मेडिकल एप्लिकेशन पोर्टल लॉन्च किया। यह ऑनलाइन पोर्टल एक वर्चुअल कार्यक्रम '"गोइंग लाइव" के दौरान जारी किया गया। यह ऑनलाइन पोर्टल, प्रत्यायन प्रक्रिया में सुगमता, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एनएबीएल के मिशन में एक बड़ा कदम है।

नया एनएबीएल मेडिकल एप्लिकेशन पोर्टल मेडिकल प्रयोगशालाओं के वास्तविक संचालन को ध्यान में रखकर पुनः विकसित किया गया है। यह प्रयोगशालाओं को एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, कम समय और अधिक सटीकता प्रदान करेगा। पोर्टल में कई सुधार शामिल हैं, जैसे पुनर्गठित एप्लिकेशन फ्लो, मानकीकृत टेम्पलेट्स, एक विस्तृत प्री-रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट, सरल और सहज यूजर इंटरफेस और मल्टी-यूजर एक्सेस फीचर, जिसके माध्यम से प्रयोगशालाएँ अलग-अलग अधिकारों के साथ कई यूजर्स को कार्य सौंप सकती हैं। इन सुविधाओं से डेटा एंट्री तेज होगी, निगरानी बेहतर होगी और पूरे मान्यता चक्र में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

क्यूसीआई अध्यक्ष, श्री जक्षय शाह ने कहा कि नए पोर्टल के माध्यम से अब ऐसे कार्य, जिन्हें पूरा करने में पहले हफ़्तों या महीनों का समय लगता था, अब सिर्फ. दो से तीन घंटे में पूरे हो सकेंगे। उन्होंने इसे भारत की क्वालिटी इकोसिस्टम में सबसे बड़े बदलावों में से एक बताते हुए कहा कि इसी मॉडल को अब अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा ताकि भारत की गुणवत्ता यात्रा में तकनीकी दक्षता, नवाचार और जवाबदेही को केंद्र में लाया जा सके।

एनएबीएल अध्यक्ष, डॉ. संदीप शाह ने कहा कि यह पोर्टल प्रत्यायन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। मल्टी-यूजर एक्सेस और सरल फीचर्स के साथ यह प्रयोगशालाओं के लिए 'व्यापार में सुगमता' को आसान बना रहा है और भारत की गुणवत्ता प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है।

इस पहल से पूरे देश की सैकड़ों मेडिकल प्रयोगशालाओं को लाभ मिलेगा। अब उन्हें आईएसओ 15189:2022 के अंतर्गत मान्यता के लिए एक पारदर्शी, कुशल और सहज डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। लॉन्च कार्यक्रम के दौरान पोर्टल का लाइव डेमो, उसकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी और देशभर की मेडिकल प्रयोगशालाओं के प्रतिभागियों के साथ एक इंटरैक्टिव प्रश्न-उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।

लागत-आधारित एमएसपीएस ढांचा

(जीएनएस)।

सरकार प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संपूर्ण देश के लिए 14 खरीफ फसलों सहित 22 अधिसूचित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करते समय, भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम-से-कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है।

नैनो यूरिया प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत शामिल किसान

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सहित नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और सभी किसानों के बीच इनके उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं

(जीएनएस)।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सहित नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और सभी किसानों के बीच इनके उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सहित नैनो उर्वरकों के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

ii. संबंधित कंपनियां नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सहित नैनो उर्वरक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराती हैं।

iii. उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से जारी मासिक आपूर्ति योजना में नैनो उर्वरकों को शामिल किया गया है।

iv. भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के माध्यम से आईसीएआर ने हाल ही में "उर्वरकों (नैनो-उर्वरकों सहित) के कुशल और संतुलित उपयोग" पर राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत गांधीनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होगी सहकारी अग्रणियों की कार्यशाला

विधानसभा अध्यक्ष अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित रहेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ह्यसहकार से समृद्धिह्न के मंत्र को साकार करने के लिए संगोष्ठी का अभिनव आयोजन

गांधीनगर, 19 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत बुधवार, 20 अगस्त को गांधीनगर में आयोजित होने वाले सहकारी अग्रणियों की कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 ह्यसहकारिताएं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैंह्न थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य सहकारी क्षेत्र में समावेशी, टिकाऊ और लचीले ढांचे तथा संगठनों का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश भर में ह्यसहकार से समृद्धिह्न के मंत्र के साथ यह अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य के सहकारिता, पशुपालन, गौ संवर्धन और मत्स्योद्योग विभाग ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार, 20 अगस्त को सुबह 11:00 बजे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी अतिथि विशेष के रूप में मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मुळुभाई बेरा, सहकारिता राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री मुकेशभाई पटेल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

इतना ही नहीं, गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री अजयभाई पटेल, इफको के चेयरमैन श्री दिलीपभाई संघाणी तथा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के चेयरमैन श्री अशोकभाई चौधरी भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में राज्य भर की जिला मध्यस्थ सहकारी बैंकों के निदेशक, जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के निदेशक और गुजकोमासोल एवं खेती बैंक के निदेशक सहित राज्य के सहकारी नेता भी हिस्सा लेंगे।

सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है

पीएलआई योजनाएं, लॉजिस्टिक्स में सुधार और जिला निर्यात केंद्र भारत को एक वैश्विक निर्यात केंद्र में बदलने में मदद कर रहे हैं

(जीएनएस)।

सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी को आगे बढ़ाना शामिल है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्य रूप से, भारत ने 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस बीच, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है, जिसे वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बड़ी मात्रा में ड्रग्स, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल और ऑटो संबंधी कलपुर्जे, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों सहित 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं लागू की हैं, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और निर्यात को बेहतर किया जा सके। इन योजनाओं ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी, रोजगार निर्माण और निर्यात में वृद्धि हुई है। इन योजनाओं ने घरेलू और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों से महत्वपूर्ण निवेश भी आकर्षित किया है।

देश भर में लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाने और उससे जुड़ी लागत कम करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) और पीएम गति शक्ति जैसी ऐतिहासिक पहल शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाना है। ये पहल बाधाओं को दूर करके, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करके और बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए तकनीक का लाभ उठाकर की गई हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आर्थिक उत्पादकता और निर्यात को बेहतर करने के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी, तेज परिवहन और संसाधनों के वांछित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकृत विकास में

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज एक हजार पांच सौ सात करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोटा-बूंदी (राजस्थान) में ग्रीन फील्ड (नया) हवाई अड्डा विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

चंबल नदी के तट पर स्थित कोटा, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, कोटा भारत के शैक्षिक कोचिंग केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है।

राजस्थान सरकार ने ए-321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 440.06 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों (पीएचपी) को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रति वर्ष यात्री वहन क्षमता बीस लाख (एमपीपीए) होगी।

इसमें 3200 मीटर ७ 45 मीटर आकार का 11/29* रनवे (हवाई पट्टी), ए-321 प्रकार के विमानों के लिए 07 पार्किंग बे (विमान पार्किंग क्षेत्र) के साथ एक एप्रन (विमान में ईंधन भरने और उनके रखरखाव का स्थान), दो लिंक टैक्सीवे, एटीसी (हवाई यातायात नियंत्रक) सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन केंद्र, कार पार्क और संबंधित कार्य स्थल शामिल हैं।

*(11/29 रनवे के चुंबकीय दिशा कोण हैं। इसका मतलब है कि जब कोई विमान रनवे पर उतरता है या टेक ऑफ करता है, तो वह 110 डिग्री या 290 डिग्री की दिशा में जा रहा होता है)

शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्रों की प्रमुखता के कारण कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अनुमानित यातायात वृद्धि का समाधान करना है।

कोटा में अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाला हवाई अड्डा मौजूद है, जहां 1220 मीटर ७ 38 मीटर आकार का एक रनवे (08/26) है, जो कोड 'बी' विमानों (जैसे डीओ-228) के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त मौजूदा एप्रन ऐसे दो विमानों के लिए उपयुक्त है। वर्तमान टर्मिनल भवन 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसकी व्यस्त समय में 50 यात्रियों को संभालने की क्षमता है।

मत्स्य पालन क्षेत्र का आधुनिकीकरण, नीली क्रांति लाने के लिए एक मुख्य योजना 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना'

(जीएनएस)।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थाई (सस्टेनेबल) और उत्तरदायी विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए एक मुख्य योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना" (PMMSY) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना पर 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा । PMMSY के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ मॉडर्न पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स, रेफ्रीजरेटिड और इंसुलेटेड वाहनों सहित फिश ट्रांसपोर्टेशन वाहन, आइस/फिश रखने वाले बक्सों के साथ मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटो रिक्शा, मारकेटिंग, फिश मारकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और फिशिंग हारबर्स के विकास/आधुनिकीकरण के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा कार्यान्वित फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फंड (FIDF) राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित पात्र संस्थाओं [एलीजीबल एंटीटीस (EEs)] को चिन्हित फिशरीज और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करती है।

विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, 734 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की 27,301 यूनिट्स जैसे कि आइस बॉक्स वाली 10924 मोटरसाइकिलें, आइस बॉक्स वाली 9412 साइकिलें, 3915 ऑटो रिक्शा, 1265 लाइव फिश वेंडिंग यूनिट्स, 1406 इंसुलेटेड ट्रक और 379 रेफ्रिजरेटेड ट्रक, 6410 फिश कियोस्क, 202 फिश रीटेल मारकेट्स, 21 होलसेल फिश मारकेट्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ढटटर के अंतर्गत 2375.25 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत 11 वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं जैसे ब्लू रिवोल्यूशन, ऋक्कऊक्र और ढटटर के अंतर्गत 9832 करोड़ रुपए की लागत से कुल 117 फिशिंग हारबर्स /फिश लैंडिंग सेंटर्स के विकास के लिए विभिन्न तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को जलवायु परिवर्तन संबंधी विषयों जैसे बढ़ते तापमान और अनियमित मानसून का मछलियों के प्रवास और प्रजनन पर पड़ने वाले प्रभावों पर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालाँकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कऊअफ), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जलवायु मापदंडों और मात्स्यिकी के बीच परस्पर क्रिया को समझने के लिए नियमित रूप से

भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा

पवई के फिल्टरपाड़ा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक पानी के बहाव में बह गया। हालांकि गनीमत रही कि बाद में उसे बचा लिया गया।

(जीएनएस)।

मुंबई में कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। सोमवार से मुंबई में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है।सड़कें नदियां बन गई हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। इसलिए प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा मीठी नदी ने मुंबईवासियों की चिंता और बढ़ा दी है। मीठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और इलाके से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। इसी बीच पवई के फिल्टरपाड़ा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक पानी के बहाव में बह गया। हालांकि गनीमत रही कि बाद में उसे बचा लिया गया।

वीडियो में क्या?

मालूम हो कि यह चौंकाने वाली घटना पवई के फुलेनगर इलाके में हुई। यहां एक युवक बाढ़ के पानी में बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि युवक को बचाया नहीं जा सका। वीडियो में दिख रहा है कि युवक दीवार पर लगी किसी चीज को पकड़कर खुद को बहाव में बहने से बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। ऊपर खड़ा एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए उसकी ओर एक रस्सी फेंकता है। उसको पकड़ने की कोशिश में युवक बह जाता है।युवक को बहते देख सहमे लोग इस दौरान वहां मौजूद लोगों की एक चीख सुनाई देती है। फिर एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो गेला, ये तो गेला... । यह एक बेहद डरावनी घटना है। इस दौरान युवक पानी के बहाव में बहते हुए कैमरे में कैद हो जाता है। वह पानी का तेज बहाव में बचने की कोशिश करता दिखाई देता है।

युवक को बचा लिया गया

दरअसल पवई फिल्टरपाड़ा और आरे को जोड़ने वाली सड़क पर मीठी नदी का तेज बहाव बह रहा है। सड़क बंद होने के दौरान युवक वहां आया और उस बहाव में फंस गया। हालांकि, गनीमत यह भी पता चला है कि युवक को बाद में बचा लिया गया। चूंकि पहले इस युवक को बचाना संभव नहीं था, इसलिए वह बह गया, लेकिन बाद में उसे बचा लिया गया।

गढ़चिरौली में उफनती नदी में बहा युवक

उधर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण उफनती नदी में बह जाने के बाद एक व्यक्ति लापता हो गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि भामरागढ़ तालुका के कोडपे गांव का 19 वर्षीय व्यक्ति सोमवार को उफनती नदी पार करते समय बह गया।

रेबीज के उपचार को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

एनआरसीपी के माध्यम से जानवरों के काटने और रेबीज के मामलों की राष्ट्रव्यापी निगरानी को मजबूत किया गया

सरकार टीकों, प्रशिक्षण और मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिकों के माध्यम से रेबीज नियंत्रण को बढ़ावा दे रही है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल के तहत एंटी-रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करता है

'वन हेल्थ' कार्यक्रम पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशुओं में रेबीज के निदान को बढ़ावा देता है।

(जीएनएस)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के माध्यम से सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी प्रकार के जानवरों के काटने की निगरानी को सुदृढ़ कर रहा है। सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के माध्यम से कुत्तों और अन्य जानवरों के काटने के मामलों और उनसे संबंधित मौतों के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधानों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तपोषण में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों का क्षमता निर्माण, रेबीज टीकों की खरीद, रेबीज और कुत्ते के काटने की रोकथाम पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का मुद्रण, डेटा प्रविष्टि सहायता, समीक्षा बैठकें, निगरानी और निरीक्षण, तथा आदर्श एंटी-रेबीज क्लीनिकों और घाव धोने की सुविधाओं की स्थापना शामिल है।

एनएचएम की राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल के अंतर्गत, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और एंटी-रेबीज सीरम (एआरएस)/रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (आरआईजी) जैसी जीवन रक्षक दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ये दवाएँ राष्ट्रीय और राज्य दोनों आवश्यक औषधि सूचियों में शामिल हैं।

गाजियाबाद पुलिस परिवार की वीर बेटी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि

(जीएनएस)।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट आज शोकाकुल है। कविनगर थाने में तैनात श्रीमती रिचा शर्मा (उप निरीक्षक, 2023 बैच) का बीती रात एक सड़क हादसे में असमय निधन हो गया। मूल रूप से कानपुर नगर निवासी श्रीमती रिचा शर्मा ड्यूटी समाप्त कर अपनी स्कूटी से लौट रही थीं। इसी दौरान अचानक सड़क पर आए एक कुत्ते से बचने के प्रयास में उनका वाहन अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। रिचा शर्मा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सेवा-भाव और सहज स्वभाव के कारण सबके बीच विशेष स्थान रखती थीं। पुलिस परिवार ने एक होनहार, जांबाज और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को खो दिया है।

परिवार की ओर से हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही, शोकाकुल परिवार को इस असहनीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करते हैं। रिचा शर्मा की सेवाएं और उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा।

वे हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगी।म0उ0नि0 रिचा सर्मा तैनाती थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की सड़क दुर्घटना के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण पुलिस विभाग को अपूर्ण क्षति हुई है,

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था एवं पुलिस परिवार द्वारा पार्थिव शरीर को कंधा देकर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धाजंलि दी गई।

4 वर्षीय अरूबा चौधरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया

गाजियाबाद के डासना यासीनगढ़ी में 4 वर्षीय अरूबा चौधरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर समारोह को यादगार बना दिया। सभी ने मिलकर केक काटा और अरूबा के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर अरूबा के पिता असलम चौधरी वह माता रेशमा चौधरी ने इस खुशी के मौके पर हर

कोई उत्साहित और खुश नजर आया।जन्मदिन के विशेष अवसर पर, आपको जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, प्यार और सफलता मिले. हम अल्लहा से दुवा करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपका आने वाला हर दिन पिछले से भी बेहतर हो. यह साल आपके लिए नई उम्मीदें, नए सपने और नई दिशाएँ लेकर आए. आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और आप यूँ ही हमेशा हँसते-मुस्कुराते रहें. यह जन्मदिन आपके जीवन में एक नई शुरूआत लेकर आए और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें.

पिछले 6 माह के दौरान चुनाव आयोग की 28 नई पहल

सुधार के स्तंभ: सभी हितधारकों से संवाद, चुनावी प्रणाली को मजबूत और शुद्ध करना, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान में सुगमता और क्षमता निर्माण

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले छह माह के दौरान 28 महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

अ- सभी हितधारकों से संवाद

ईआरओ, डीईओ और सीईओ द्वारा सर्वदलीय बैठकें: देशभर में ईआरओ, डीईओ और सीईओ द्वारा कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं। इनमें 40 बैठकें सीईओ, 800 बैठकें डीईओ और 3879 बैठकें ईआरओ ने कीं। इन बैठकों में विभिन्न राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व से बैठकेंझ्र आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं से लगातार संवाद कर रहा है। अब तक 20 बैठकें आयोजित की चुकी हैं।

इ- चुनावी प्रणाली को मजबूत और शुद्ध करना

निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाना - 476 दलों की पहचान की गई, जिनमें से 334 दलों को पहले ही सूची से हटा दिया गया।

28 हितधारकों की भूमिकाओं की पहचान और भूमिकाओं का निर्धारण - संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960, चुनाव आचार नियम 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है।

बीएलओ (बीएलओ) के लिए फोटो पहचान पत्रझ्र पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मानक पहचान पत्र जारी किए गए।

ईवीएम माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन - परिणामों की घोषणा के बाद 5% ईवीएम में बर्न मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच और सत्यापन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई।

कानूनी सलाहकारों और सीईओ की राष्ट्रीय सम्मेलनझ्र अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपनी कानूनी प्रतिनिधित्व की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए।

चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकेंझ्र जून 2025 में आईडीईए स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की, ताकि चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक सहयोग में भारत की पुरानी साझेदारी को और मजबूत किया जा सके।

उ- प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग

एकल डिजिटल पोर्टल - ईसीआईएनईटीझ्र मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों सहित अपने हितधारकों के लिए 40 से अधिक ऐप्स/वेबसाइटों को एक ही पोर्टल में शामिल किया गया।

मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंगझ्र यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कि महत्वपूर्ण गतिविधियां बिना किसी गड़बड़ी के सुचारू रूप से हों।

मतदाता उपस्थिति का रियल-टाइम अपडेटझ्र मतदान दिवस पर हर दो घंटे में पीठासीन अधिकारी ईसीआईएनईटी ऐप पर डेटा अपलोड करेंगे, ताकि मतदान रुझानों के अपडेट होने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।

डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट्सझ्र सभी हितधारकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली।

वीवीपैट (श्ढअळ) का अनिवार्य मिलानझ्र फॉर्म 17सी और ईवीएम डेटा के बीच गलत मिलान के हर मामले में और जहां मॉक पोल डेटा गलती से मिटाया नहीं गया था, वहां वीवीपैट पर्ची की गिनती।

ऊ- मतदाता सूची की शुद्धता

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षणझ्र बिहार में मतदाता सूची को शुद्ध किया गया ताकि कोई भी योग्य मतदाता न छूटे और कोई भी अयोग्य नाम न रहे।

उपचुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणझ्र लगभग दो दशकों में पहली बार 4 राज्यों में हाल ही में